तिब्बत के इतिहास में नया मोड़ आने से चीनी सरकार की प्रतिकिया

इस साल 10 मार्च को परम पावन दलाई लामा के वकत्तव्य में 369 साल से चल रहे गांदेन फोड्रांग के धार्मिक प्रशासन को भंग कर लोकतंत्रिक व्यावस्था से तिब्बती जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को राजनितिक अधिकार सोंपने एवं तिब्बती (राजपत्र) संविधान में भी परिवर्तन होने से चीनी सरकार की प्रतिक्रिया देखने लायक हो गई है। वैसे अब तक चीनी सरकार तिब्बत का मुद्दा परम पावन दलाई लामा का निजी मुद्दा बताते आए हैं, और दलाई लामा के इस एतिहासिक कदम से चीनी सरकार को करारा जवाब मिला है। जिस पर चीनी सरकार द्वारा कड़े विरोध एवं तीखी टिप्पणी भी हुई।

गौरतलब है कि चीनी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी पुनर्जन्म के आधार पर दलाई लामा के चुनाव की प्रणाली को लेकर है। जिसपर दलाई लामा स्वयं ने ही अमरिका के एक इण्टरव्यू में ही सपष्ट कर दिया था कि "मैरे पुनर्जन्म के चुनाव का अधिकार सिर्फ मुझे है, और किसी पर नही", जो एक तर्कसंगत विचार है। चीनी सरकार के दमनकारी स्वरुप का उदाहरण दें तो इनकी कटुता को निर्दयी एवं निष्ठुर के रुप में कहें तो उसमें कोई दौ राय नही होगी। जैसे 2008 के दंगो के बाद तिब्बत पर चीनी सरकार की क्रूर नीति, हाल में किर्ति मठ में चीनी दमन के ताकत की ज़ोरअज़माइश, तिब्बती लेखकों की गिरफतारी एवं पड़ोसी देशों को तिब्बत के खिलाफ इस्तेमाल करना आदि चीनी दमनकारीयों के नीतियों का कड़वा सच है।

सन 1979 से चीन से चल रहे सीधी वार्ताओं का अबतक कोई साकारात्मक नतीजा निकल नहीं पाया है और तिब्बत में मौजूदा हालात बद से बदत्तर होती जा रही है। तिब्बत में मानवाधिकार हनन अब भी जारी है।हालांकि परम पावन दलाई लामा के अपने राजनितिक त्याग के एतिहासिक कदम पर चीनी सरकार के संयुक्त मोर्चे के उप मंत्री (Zhu Weiqun) द्वारा दिए गए हताशा भरी टिप्पणीयों में कहा कि "चीन तिब्बत कि समस्या पर दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ सीधे वार्ता करेगी और भविष्य में किसी भी अध्यात्मिक नेता से वार्ता सीमित रहेगा" जो चीन के बड़ते मुशकिलों का संकेत है और चीन दलाई लामा के हर एक कदम पर शब्दबाण एवं प्रतिक्रिया दिखाने पर मजबूर हो चुका है। यहां तक कि नवनिर्वाचित कलोन त्रिपा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कानून के फैलो डा0 लोबसांग सेंग्ये को भी आतंकवादी करार दिया, जो एक अतर्किक बयान है।

हाल ही में चीन द्वारा नेपाल में 3 अरब डॉलर के आर्थिक निवेश से नेपाल के पर्यटक एवं तीर्थ स्थल लुंबीनी को "शेश विकास ज़ोन" बनाने कि योजना को नेपाल सरकार द्वारा ठुकराने से चीनी नीतियों का भांडाफोड़ हुआ है। चीन के ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़ने की कूटनीति भी किसी से छुपी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से बहती है और जिसपर दुनिया के 40 प्रतिशत से अधिक अबादी के लोग निरभर है। यह भी कहा जा रहा है कि चीन की ब्रह्मपुत्र जलापूर्ति नीति न भू–राजनिति से प्रेरित है, न विचारपद्धति से, यह बुद्धिवादों से उत्तपन्न हुई एक आर्थिक नीति है, जिसके द्वारा चीन अपनी आर्थिक स्तिथि मजबूत कर पूरे एशिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है।

तिब्बत के इतिहास में पहली बार ऐसा पड़ाव आया है जिससे चीनी राजनितिक व्यावस्था पर दुरगामी प्रभाव हो सकता है। विश्व के कई देश जैसे टुनिशिया, अलजीरिया, इजिप्ट, बहरैन, लीबिया आदि में जारी जनांदोलन को देखते हुए लोकतंत्रिक तरीके से निर्वासित तिब्बती प्रशासन के राजनितिक एवं संसद को कार्यकारी शक्तियां सौंपने का दलाई लामा के कदम से चीन की कम्युनिस्ट प्रशासन में भी इसी तरह की मांग को बड़ावा मिल सकता है। हालांकि चीनी सरकार द्वारा यह विश्वास जताया गया है कि एसी चुनौतीयों का सामना अपने आंरिक नियांत्रण के द्वारा करेगा। निर्वासित तिब्बतियों को दीर्घकालिक एवं स्थायी संस्थानिक व्यावस्था और लोकप्रिय जवाबदेही प्रदान कर दलाई लामा ने अपने न रहने की स्थिति में किसी भी तरह की अस्थिरता और अव्यवस्था को खत्म कर दिया है। दलाई लामा के मौजुदा कदम से चीनी सरकार द्वारा अगले दलाई लामा चुनने के इरादे को भी कम कर दिया है और उनके इस कदम से चीनी सरकार को अपना केन्द्रबिन्दू बदलना पड़ सकता है। जो निर्वासित तिब्बती एवं तिब्बती प्रशासन के लिए एक नई उपलब्धि सिद्ध हो सकती है।

- तेनजिन नोरबू

तिब्बत में 'आतंक का शासन': दलाई लामा

पवित्र बौद्ध त्योहार साका दावा के दिन 15 जून को 9 तिब्बतियों ने कार्डजे के निचले शहर में विरोध प्रदर्शन किए। भारत स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) ने दो भिक्षुणियों छोसांग (31 साल) और पेलट्रुक (34 साल) को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है।

(आरएफए, 5 जून)

परमपावन दलाई लामा ने कहा है कि चीनी प्रशासन द्वारा तिब्बत के भीतर 'भय का शासन' और 'आतंक का शासन' कायम किया जा रहा है। तिब्बत में सुरक्षा बंदोबस्त सख्त कड़ने और वहां की शिक्षा एवं संस्कृति पर हमले का उदाहरण देते हुए परमपावन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 1979 से ही चीन से चल रही सीधी वार्ताओं का 'कोई सकारात्मक नतीजा' नहीं निकला है और तिब्बत के भीतर की स्थिति लगातार बदतर और बुरी होती जा रही है।

अमेरिका के डब्ल्यूएचएयूटी–टीवी पर प्रसारित टीवी कार्यक्रम ''आइडियाज इन एक्शन विद जिम ग्लासमैन'' में दिए इंटरव्यू में दलाई लामा ने कहा, "तिब्बत में शिक्षा पर काफी अंकुश लगाया गया है और राजनीतिक पुनर्शिक्षा अभियान को तेज कर दिया गया है। तिब्बतियों में यह चिंता पनपी है कि अब एक 'अर्द्ध सांस्कृतिक क्रांति' वापस आ रही है।" दलाई लामा ने कहा कि चीन की 'सख्त, संकुचित सोच वाली और अदूरदृष्टि वाली नीतियों' की वजह से ही साल 2008 में तिब्बत में भयानक दंगों की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि अब चीनी प्रांतों के तिब्बती क्षेत्रों में 'और भी सख्ती' बरती जा रही है। दलाई लामा ने कहा कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार सभी तिब्बती पुस्तकें हटा दी गई हैं और विद्यार्थियों को सिर्फ वही पुस्तकें रखने का आदेश दिया जा रहा है जो कि आधिकारिक रूप से इस्तेमाल की जाती हैं। दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत में रहने वाले तिब्बती, कम्युनिस्ट एकाधिकारवादी शासन के तहत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलना 'असंभव' हो गया है। उन्होंने कहा, "ऐसे में लोगों के सामने विरोध प्रदर्शन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनकारियों को परेशानी खड़ा करने वाला मानते हुए गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें गंभीर रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

तिब्बत से आए वीडियो से खुलासा, तिब्बत में जमकर हो रहे विरोध प्रदर्शन

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 7 जून)

चार भिक्षुओं के एक समूह ने 8 मई, 2010 को पूर्वी तिब्बत के खम प्रांत में स्थित न्यागरांग में लगातार चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के दौरान 'परमपावन दलाई लामा जिंदाबाद', 'तिब्बत आज़ाद है' और 'परमपावन दलाई लामा को तिब्बत बुलाओ' जैसे नारे लगाए। इनमें से तीन भिक्षु गुरु मठ के और एक जामजोर मठ के थे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को हासिल एक वीडियो से यह जानकारी मिली है। इन चारों भिक्षुओं 22 साल के आपो टाशी, 19 साल के सेरिंग ग्याल्तसेन, 22 साल के सेरिंग वांगचुक और रिंगजिन दोरजी ने पत्रक वितरित किए और तिब्बती राष्ट्रीय झंडे फहराए। इस प्रदर्शन के कुछ ही मिनटों के बाद प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए चीनी पुलिस पहुंच गई, लेकिन स्थानीय नागरिकों ने पुलिस का रास्ता रोके रखा जिससे तीन भिक्षु मोटरसाइकिल पर बैठ कर भाग लिए। लेकिन चौथे भिक्षु को पुलिस ने पकड़ लिया और उसकी मोटरसाइकिल को पुलिस ने तोड़ दिया। गौरतलब है कि साल 2008 से ही तिब्बत के न्यागरांग और अन्य इलाकों में तिब्बतियों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। चीन सरकार द्वारा जबरन 'देशभक्ति शिक्षा' को थोपे जाने के विरोध में निचले न्यागरांग में रहने वाले तिब्बती नागरिकों ने रोष का प्रदर्शन किया। यह चीन सरकार का एक ऐसा अभियान है जिसके तहत तिब्बतियों को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वे दलाई लामा को अपमानित करें और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का समर्थन करें। ऊपरी न्यागरांग के निवासियों ने इसके विरोधस्वरूप खेती का ही बहिष्कार कर दिया है। सरकारी आदेश न मानने वाले कई तिब्बती नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मार्च, 2009 में पत्रक वितरित करने और उसे चिपकाने के आरोप में एक तिब्बती नागरिक पेमा येशी को दो साल के लिए विलंबित मौत की सजा सुनाई गई है। दो अन्य तिब्बती नागरिकों सोनम गोनपो और सांगत्सोग को क्रमशः आजीवन कारावास और 16 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद अप्रैल महीने में तिब्बत के क्याछु थंगक्या इलाके के नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया जिस पर चीनी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। साल 2009 और 2010 में खावा लुंगरी के नागरिकों ने एक पवित्र पर्वत से सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के दोहन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

तिब्बती लेखक को 4 साल की सजा

(4 जून, फायूल)

प्रभावी तिब्बती लेखक ताशी राबटेन (पुकारने का नाम–थेउरांग) को पूर्वी तिब्बत की एक चीनी अदालत द्वारा 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। गत 2 जून को नाबा माध्यमिक जन न्यायालय ने ताशी राबटेन के कुछ पारिवारिक सदस्यों और मित्रों की मौजूदगी में उन्हें यह सजा सुनाई। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार प्रतिबंधित साहित्यिक पत्रिका 'शार डुंगरी' (पूर्वी बर्फीला पहाड़) के संपादक टाशी राबटेन को 'देश को बांटने वाली भड़काऊ गतिविधियों' में शामिल होने के आरोप में यह सजा सुनाई है।

लांझू के उत्तर–पश्चिम राष्ट्रीयता विश्वविद्यालय के छात्र टाशी को 6 अप्रैल, 2010 को हिरासत में लिया

गया था और इसके छह महीने के बाद उन्हें पूर्वी तिब्बत के नाबा के बरखाम काउंटी में देखा गया। सरकारी अधिकारियों ने तिब्बत के भीतर साल 2008 में हुए विरोध प्रदर्शनों पर उनकी रिपोर्ट और उनकी पुस्तक 'रक्तरंजित लेखन' की प्रतियों को जब्त किया है जबकि इन्हीं से ताशी को बुद्धिजीवियों और आम पाठकों में बहुत ज्यादा सम्मान और लोकप्रियता हासिल हुई है।

टाशी राबटेन तिब्बती प्रांत आमदो के सिचुआन प्रांत में स्थित नाबा के जोएगे काउंटी के निवासी हैं और साल 2010 में ही ग्रेजुएट होने वाले थे। इसके पहले इस साल तीन अन्य तिब्बती लेखकों को चार साल जेल की सजा सुनाई गई और प्रख्यात तिब्बती बुद्धिजीवी ताग्याल को पिछले साल अक्टूबर में छह साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद जमानत पर रिहा किया गया है। तिब्बती बुद्धिजीवियों और कलाकारों पर चीन सरकार द्वारा जारी दमन की अंतरराष्ट्रीय जगत में बड़े पैमाने पर आलोचना हुई है।

धन के बल पर तिब्बती भिक्षुओं को नहीं खरीद सका चीन

(रेडियो फ्री एशिया, 3 जून)

पुलिस छावनी बना दिए गए कीर्ति मठ के तिब्बती भिक्षुओं ने चीनी प्रशासन द्वारा दिए जा रहे धन को लेने से इनकार कर दिया है जिससे साफ तौर पर उनके जमीर को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। भारत में रहने वाले तिब्बती भिक्षुओं कानयांग सेरिंग और लोबसांग येशे ने कीर्ति मठ के आसपास रहने वाले अपने संपर्कों के हवाले से बताया, "मध्य मई के आसपास एक दिन चीनी प्रशासन ने घोषणा की कि वह कीर्ति मठ के हर भिक्षु को 800 युआन (करीब 5,515 रुपए) का मासिक भत्ता देगा। लेकिन इस समाचार को सुनते ही भिक्षुओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और संकल्प लिया कि कोई भी सरकारी भत्ते को हाथ नहीं लगाएगा।" इसके बाद 26 मई को अधिकारियों ने एक पखवाड़े का 400 युआन का भत्ता वितरित करने का प्रयास किया लेकिन कुछ भिक्षुओं ने यह धन हाथ में लिया और नोटों के टुकड़े–टुकड़े कर उस जमीन पर बिखेर दिया। भिक्षुओं ने सरकारी अधिकारियों से कहा कि यदि चीन के कानून या संविधान में इस तरह धन ठुकराने और नोट फाड़ने के लिए कोई दंड है तो वे उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। भिक्षुओं ने इस बात की भी शिकायत की कि दो माह के बाद भी उनके मठ में लगातार चीनी सुरक्षा बलों और सशस्त्र पुलिस बलों ने डेरा डाल रखा है और उनके दैनिक शिक्षण एवं धार्मिक गतिविधियों में प्रशासन दिन–प्रतिदिन दखल दे रहा है।

पूर्वी तिब्बत में विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में 60 से ज्यादा तिब्बती गिरफ्तार

(29 जून, आरएफए)

पूर्वी तिब्बत के कार्डजे में चीनी प्रशासन ने चीनी शासन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। यह विरोध 6 जून से शुरू हुए थे और 17 जून के बाद इनमें काफी तेजी आ गई। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोगों में भिक्षु, भिक्षुणियां और साधारण जनता है। तिब्बत की आज़ादी की मांग करने के अलावा विरोध प्रदर्शनकारियों ने उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर भी नारे बुलंद किए जिन्हें पिछले साल कार्डजे में गिरफ्तार किया गया था। चीनी सुरक्षा बलों ने 17 से 19 जून तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा उपायों में भारी बढ़त की है।

इसके बाद 6 जून को करीब 18 साल के दो भिक्षु सेवांग ताशी और गुरमे सोनम ने परमपावन दलाई लामा जिंदाबाद, उन्हें तिब्बत वापस बुलाने और तिब्बत को आज़ाद करने के नारे लगाए और कार्डजे कस्बे के दो सेंगे में हवा में पत्रक उछाले। इसे देखते ही चीनी पुलिस के जवान दौड़ पड़े और उन्होंने दोनों को पहले लोहे की छड़ी से पीटा और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 7 जून को वुजर फुंत्सोग नाम के एक भिक्षु अचानक कस्बे के बीचोबीच आ गए और उन्होंने भी जोर–जोर से ऐसे नारे लगाने शुरू कर दिए। उनको भी बुरी तरह पीटा गया और हिरासत में ले लिया गया।

इसी प्रकार 9 जून को एक भिक्षुणी सेयांग ने अकेले विरोध प्रदर्शन किया और 10 जून को लामड्रैक ननरी की दो भिक्षुणियां और कार्डजे मठ के एक भिक्षु ने कार्डजे के निचले सिरे पर स्थित एक थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। रिगा और शोगा नाम की दोनों भिक्षुणियां करीब 20 साल की हैं और भिक्षु का नाम गोवांग है। विरोध प्रदर्शनों के बाद तीनों को जमकर पीटा गया और हिरासत में ले लिया गया। 13 जुलाई को खत्म हफ्ते में कुल 17 तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें कार्डजे के निचले शहर स्थित केंद्र में हिरासत में भेज दिया गया। इस जेल में बेरी मठ, कार्डजे मठ, गेत्से ननरी और खांगमार मठ के बहुत से भिक्षु–भिक्षुणी पहले से ही बंद थे। पवित्र बौद्ध त्योहार साका दावा के दिन 15 जून को 9 तिब्बतियों ने कार्डजे के निचले शहर में विरोध प्रदर्शन किए। भारत स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) ने दो भिक्षुणियों छोसांग (31 साल) और पेलट्रुक (34 साल) को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। इन दोनों ने 18 जून को सुबह करीब 9 बजे कार्डजे के मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन किया

"चीन सरकार यह बताए कि जिन लोगों को जबरन गायब किया गया है उनकी क्या हालत है और उन्हें कहां रखा गया है, उन तिब्बती भिक्षुओं के समूह के बारे भी खुलासा किया जाए जिनका कुछ नहीं पता चल पा रहा कि वे कैसें हैं और उन्हें कहां रखा गया है।"

"हमने बहुत से विदेशियों की यात्रा को रद्द किया है, लेकिन हम इसके पीछे की वजह नहीं जानते। शायद इसकी कुछ राजनीतिक वजह है।"

था। इसके बाद 28 जून को सुबह गेमाङ्रा मठ की दो भिक्षुणियों कुंगा छोजोम (22 साल) और डेकी ल्हामो (18 साल) ने कार्डजे काउंटी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये दोनों भिक्षुणियां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कस्बे में रात के समय घुस गईं। कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कस्बे में जबर्दस्त सुरक्षा बंदोबस्त थे। उसी दिन कार्डजे टाउन में विरोध प्रदर्शन करते हुए एक तिब्बती नागरिक कर्मा येशी को गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 29 जून को खबर दी है कि कार्डजे में इस महीने विरोध प्रदर्शन की कम से कम 15 घटनाएं देखी गईं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कार्डजे के दो भिक्षुओं को 22 जून को तिब्बत की राजधानी ल्हासा के व्यस्त बारखोर बाजार में विरोध प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ल्हासा में यह मार्च 2008 के बाद संभवतः पहला विरोध प्रदर्शन था। चीनी प्रशासन ने जून के अंतिम हफ्ते से जुलाई के अंतिम हफ्ते तक मध्य तिब्बत में विदेशियों के जाने पर पाबंदी लगा रखी थी।

इस इलाके में रहने वाले एक सूत्र ने बताया कि चीनी पुलिस ने कार्डजे कस्बे में दो तरफ से प्रवेश को पूरी तरह से रोक रखा है। उसने बताया कि उस इलाके में भिक्षुओं और भिक्षुणियों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। किसी बाहरी गांव या चरवाहा क्षेत्र से आने वाले तिब्बती को कार्डजे में घुसने से पहले स्थानीय अधिकारियों की इजाजत लेनी पड़ रही है।

कीर्ति मठ में अब भी पूरी ताकत से जारी है चीनी दमन

सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए जाने से पहले इन तिब्बती चालकों की जमकर पिटाई की गई।

(28 जून, आरएफए–आईसीटी)

चीनी शासन के खिलाफ एक तिब्बती भिक्षु द्वारा आत्मदाह कर लेने की घटना के बाद पूर्वी तिब्बत के नाबा में स्थित कीर्ति मठ के तिब्बती भिक्षु लगातार चीनी शासन के बंदूकों के निशाने पर हैं। इस मठ को सैकड़ों पुलिस कर्मियों, सैनिकों और सरकारी अधिकारियों ने घेर रखा है और सुरक्षा कैमरा लगाकर भिक्षुओं की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नाबा में स्थानीय लोगों से लगातार संपर्क में रहने वाले दो निर्वासित भिक्षुओं कानयाग सेरिंब और लोबसांग येशे ने बताया, "मठ को करीब 400 सरकारी अधिकारियों ने घेर रखा है इसके अलावा पुलिस, सेना और विशेष सुरक्षा बलों के जवान सुबह, दोपहर और रात लगातार भिक्षुओं की हर गतिविधि पर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि भिक्षुओं को डराकर रखने के लिए समूचे परिसर में जगह–जगह कैमरे और अन्य उपकरण लगाए गए हैं। उन्होंने बताया, "कभी–कभी कुछ भिक्षुओं को कस्बे में या कहीं और जाने दिया जाता है, लेकिन उनके पीछे कोई न कोई अधिकारी लगा रहता है।"

सूत्रों के अनुसार कीर्ति मठ में हुई घटना से पहले यहां करीब 2500 भिक्षु रहते थे। खास त्योहारों के मौके पर तो भिक्षुओं की संख्या बढ़कर 2700 तक हो जाती थी। लेकिन अब वहां से 300 भिक्षुओं को जबर्दस्ती कहीं दूर ले जाया गया है और कुछ सौ को निकाल दिया गया है वे वहां से भाग गए हैं। इस प्रकार अब वहां मठ में करीब 2000 भिक्षु ही बचे हैं। एक मानवाधिकार संगठन तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान (आईसीटी) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि नई सूचनाओं के अनुसार "मठ पर घेरा डाले हुए सुरक्षा बलों की उपस्थिति, गायब कर दिए जाने के खतरे, प्रताड़ना और धर्म के पालन को कठिन या असंभव बनाने वाले देशभक्ति शिक्षा अभियान के साथ सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई" की वजह से भिक्षु कीर्ति मठ को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आईसीटी की रिपोर्ट के अनुसार मठ के भीतर बने नए 25 कमरों वाले मीटिंग हॉल पर पूरी तरह से सेना और पुलिस का कब्जा है और पूरे परिसर में अन्य जहां भी कमरे या डॉरमेटिरी खाली हैं, उन पर सेना, पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने कब्जा जमा रखा है। चीन सरकार ने गत 8 जून को जेनेवा में जबरन या बिना मर्जी के लोगों को गायब कर देने पर संयुक्त राष्ट्र कार्यसमूह द्वारा जारी मजबूत अपील को भी खारिज कर दिया है। कार्यसमूह ने अपील की थी, "चीन सरकार यह बताए कि जिन लोगों को जबरन गायब किया गया है उनकी क्या हालत है और उन्हें कहां रखा गया है, उन तिब्बती भिक्षुओं के समूह के बारे भी खुलासा किया जाए जिनका कुछ नहीं पता चल पा रहा कि वे कैसें हैं और उन्हें कहां रखा गया है।"

नौकरी में भेदभाव पर तिब्बत में प्रदर्शन, टकराव

(आरएफए, 17 जून)

केंद्रीय तिब्बत के शिगास्ते और पूर्वी तिब्बत के लिथांग में तिब्बती ट्रक चालकों और चीनी दंगा पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ है। यह टकराव तब शुरू हुआ जब वायदे के विपरीत सड़क एवं रेलवे परियोजनाओं में काम तिब्बतियों को देने की बजाए चीनी कंपनियों में काम करने वाले चालकों को दे दिया गया। इस इलाके में संपर्क रखने वाले और भारत में निर्वासन में रहने वाले तिब्बती लोबसांग गावा ने बताया, "गत 1 जून को करीब 100 तिब्बती चालकों ने लिथांग काउंटी के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया।" गावा ने बताया कि चीनी अधिकारियों ने चीन की 24 कंपनियों को काम सौंपा है जो अपने साथ चीनी श्रमिक लेकर आए हैं, इसे देखकर ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। उस इलाके में रहने वाले एक तिब्बती ने बताया कि अप्रैल माह में शिगास्ते के निकट रिनपुंग काउंटी के नजदीक तिब्बती ट्रक चालकों और चीनी ट्रक चालकों के बीच टकराव हुआ

था। इस इलाके में रहने वाले सूत्र ने बताया, "चीनी ट्रक चालकों ने सरकारी अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी जिसके बाद शिगास्ते से 15–20 गाड़ियों में पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने 10 तिब्बती ट्रक चालकों को हिरासत में ले लिया। सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए जाने से पहले इन तिब्बती चालकों की जमकर पिटाई की गई।

चीन ने तिब्बत में विदेशियों के जाने पर रोक लगाई

(रायटर्स, 16 जून)

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 90वीं वर्षगांठ 1 जुलाई के पहले चीन ने तिब्बत में विदेशियों के जाने पर रोक लगा दी है। अस्थिरता या एक पार्टी शासन के प्रति किसी भी संभावित खतरे के प्रति बेहद संवदेनशील चीन अपने नस्लीय सीमा क्षेत्र (जिसे वह 'स्वायत्तशासी क्षेत्र' कहता है) में विदेशियों को लेकर सतर्क है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा के एक बड़े होटल के एक ट्रैवल एजेंट ने बताया, "90वीं वर्षगांठ के उत्सवों के नाते यह एक नया नियम बनाया गया है। यहां तक कि टुअर ग्रुप में भी विदेशी वहां नहीं जा सकते।" बीजिंग की एक ट्रैवल एजेंसी ने बताया कि कई महीने पहले ही यह अधिसूचना आ गई थी कि जुलाई माह में विदेशियों को तिब्बत नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि अगस्त में तिब्बतियों के महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर यह प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। एजेंट ने कहा, "हमने बहुत से विदेशियों की यात्रा को रद्द किया है, लेकिन हम इसके पीछे की वजह नहीं जानते। शायद इसकी कुछ राजनीतिक वजह है।" गौरतलब है कि मई माह में चीन ने विदेशियों को कहा था कि वे उसके विशाल उत्तरी क्षेत्र आंतरिक मंगोलिया में अशांति की तस्वीरें दुनिया को न दिखाएं। एक मंगोलियाई चरवाहे की ट्रक से कुचलकर मौत होने के बाद मंगोलियाई लोगों द्वारा हुए भारी विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया भर का ध्यन आकर्षित किया था। विदेशियों को हमेशा ही तिब्बत जाने के लिए इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन सरकार समय–समय पर कई तिब्बती क्षेत्रों में विदेशियों के जाने पर रोक लगाती रहती है।

अप्रैल माह में चीन ने तिब्बत के सिचुआन प्रांत में विदेशियों के जाने पर रोक लगा दी थी जहां के कीर्ति मठ के एक युवा भिक्षु द्वारा चीनी शासन के खिलाफ आत्मदाह कर लेने के बाद चीनी प्रशासन ने मठ का घेराव कर लिया था।

तिब्बतियों पर कार्रवाई के लिए नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है चीन

(इकनॉमिक टाइम्स, 29 जून)

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में अपने पांव मजबूती से जमाने के बाद चीन अब नेपाल की विदेश नीति को अपने प्रभाव में लेने का सचेत प्रयास कर रहा है। चीन ने नेपाल सरकार पर यह दबाव बनाया है कि वह नेपाल के रास्ते धर्मशाला जाने की कोशिश करने वाले तिब्बतियों को रोके और उसने नेपाल में तिब्बतियों की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा है। चीन को नेपाली उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कृष्ण बहादुर महरा के रूप में एक अच्छा सहयोगी मिल गया है जो माओवादी हैं और चीन सरकार के काफी करीब हैं। महरा के नेतृत्व में तिब्बती आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित किया गया है और चीन सीमा पर स्थित नेपाली सेना के जवान नेपाल के रास्ते से धर्मशाला आने की कोशिश करने वाले तिब्बतियों को पकड़ कर वापस चीन भेज देते हैं। एक वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारी ने बताया, "हमें इस बात की जानकारी मिली है कि पिछले दो–तीन महीनों में भारत आने की कोशिश कर रहे तिब्बतियों को नेपाल पार नहीं करने दिया जा रहा है।" इसके अलावा महरा ने साफ तौर पर निर्देश दे रखा है कि नेपाल में चीन विरोधी गतिविधियों और प्रदर्शनों को हतोत्साहित किया जाए। नेपाली सरकार के समर्थक रुख को देखते हुए हाल में नेपाल में चीन के नए राजदूत यांग हुलान ने महरा के साथ मुलाकात की और इस बात की चिंता जताई कि नेपाल के तिब्बती शरणार्थी 1 जुलाई को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वर्षगांठ पर 'चीन विरोधी' प्रदर्शन कर सकते हैं। महरा के प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने चीनी राजदूत को आश्वस्त किया कि नेपाल अपनी जमीन पर ऐसी किसी भी गतिविधि को इजाजत नहीं देगा। महरा की चीन सरकार से नजदीकी का पिछले साल तब खुलासा हुआ जब हांगकांग के एक चीनी एजेंट से उनकी बातचीत का कथित ऑडियो टेप लीक हो गया। इस टेप में महरा नेपाल में प्रधानमंत्री के चुनाव को मनमाफिक कराने के लिए चीनी एजेंट से 500 करोड़ रुपए घूस मांग रहे थे। तिब्बती शरणार्थियों के प्रति नेपाल के रवैए के प्रति अभी भारत सरकार ने किसी भी तरह का विरोध जताने से दूरी बना रखी है, लेकिन तिब्बतियों के आंदोलन को खुलकर समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल के सामने इस मसले को उठाने की अगुवाई की है। अमेरिका ने भी नेपाली अधिकारियों से कहा है कि वे तिब्बती शरणार्थियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के मागर्दर्शन में हुए समझौते का सम्मान करें। इस समझौते में कहा गया है कि नेपाल तिब्बती बच्चों का पंजीकरण करेगा और उन्हें या तो नेपाल में जमीन देगा या उन्हें धर्मशाला (भारत) जाने के लिए सुरक्षित रास्ता देगा।

लीक हुए दस्तावेजों से हुआ चीनी दुष्प्रचार नीति का खुलासा

(फायूल–इनफॉर्मेशन, 29 जून)

डेनमार्क के समाचारपत्र *इनफॉर्मेशन* ने चीन सरकार

इसमें कहा गया है कि चीन में रहने वाले विदेशी पत्रकारों और एनजीओ पर सख्ती की जाए, पश्चिमी संस्कृति के उत्पादों के चीनी बाजार में आने पर ज्यादा नियंत्रण रखा जाए और वरोधी विचारकों को विदेशी मीडिया में अपने विचार पेश करने से रोका जाए।"

चीन जिस तरह से नेपाली नेतृत्व पर दबाव बनाने में सक्षम हुआ है, नेपाल के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक विकास रणनीति में घुसपैठ कर चुका है और नेपाल में रहने वाले करीब 20,000 निर्वासित तिब्बतियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगा रहा है उससे भारत की चिंता बढ़ गई है।

के एक उच्च स्तर के दस्तावेंजों के कुछ अंश प्रकाशित किए हैं, जिसमें उसके शीर्ष अधिकारी ने कहा है, "तिब्बत की आज़ादी के समर्थक और सीक्यांग की अलगाववादी ताकतें जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय जनमत का समर्थन हासिल कर रही हैं हमें उनकी इस ताकत को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यह लीक हुए दस्तावेज जनवरी से मध्य मार्च के बीच के हैं। यह दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च अंग केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी किया गया है और इसे सभी प्रांतीय सरकारों और चीनी जनमुक्ति सेना के सभी मुख्यालयों को इस संदेश के साथ भेजा गया है कि "केंद्रीय कमेटी के कॉमरेड और राज्य परिषद के नेताओं ने जिस बात पर सहमति जताई है उन्हें निश्चित रूप से उस नीति को लागू करने के लिए कठोर मेहनत करनी चाहिए।" इस दस्तावेज से यह खुलासा होता है कि चीन सरकार एक तरह का दोहरा खेल खेल रही है और बाहरी दुनिया के सामने वह इन इलाकों की जिस तरह की तस्वीर पेश करना चाहती है और जिस तरह का शासन चलाना चाहती है उसमें खाई बढ़ती जा रही है। कम्युनिस्ट शासन के प्रोपेगंडा साधनों को यह निर्देश दिया गया है कि वे दूसरे देशों के सामने चीन को शांतिप्रिय, लोकतंत्र की ओर बढ़ने वाले और दुनिया के लिए खुले देश के रूप में पेश करें। लेकिन इस दिखावे के पीछे चीनी जनता और समाज पर इसकी पकड़ कठोरता के नए स्तरों तक सख्त होती जा रही है।

काफी समय से पश्चिमी दुनिया में यह उम्मीद रही है कि चीन के तीव्र आर्थिक विकास से स्वाभाविक रूप से वह आगे चलकर राजनीतिक उदारीकरण की ओर बढ़ेगा और चीनी नागरिकों को ज्यादा आज़ादी और नागरिक अधिकार हासिल होंगे। लेकिन लीक दस्तावेजों से तो यह पता चलता है कि चीन अपनी हर संभव ताकत का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है कि ऐसा कुछ न होने पाए।

अखबार में छपे दस्तावेजों के अनुसार प्रोपेगंडा मंत्रालय के एक पेपर में कहा गया है, "चीनी और विदेशी वेबसाइट पर आने वाली सभी तरह की अवैध और हानिकारक सूचनाओं को पूरी तरह से रोका जाए और उन्हें गायब किया जाए।"

दस्तावेजों में प्रांतीय सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे जनमत को कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में मोड़ने के लिए स्थानीय सेल बनाएं जो चैट रूम एवं ब्लॉग पर होने वाली चर्चाओं में हिस्सा लें। सांस्कृतिक क्रांति के दिनों की याद ताजा कराने वाले इन दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कार्य स्थलों, गांवों और टाउनशिप में जासूसों की फौज तैनात की जाए जो गुमराह नागिरिकों का पता लगाएं। माओत्से तुंग के युग की याद दिलाते इस प्रोपेगंडा दस्तावेज में चीनी ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि वे उसके प्रगति और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रहे हैं। *इंफॉर्मेशन* में छपे दस्तावेज में कहा गया है, "चीन के भीतर और बाहर की शत्रु ताकतें हमें बदलने की सलाह दे रही हैं। वे हर साधन से हमारे विकास को सीमित करने, हमारी छवि को धूमिल करने और हमारी विचारधारा एवं संस्कृति को दूषित करने का प्रयास कर रही हैं। वे हम पर इस बात के लिए दबाव बना रही हैं कि हम पश्चिमी मूल्यों और पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था को अपना लें।

विरोधी स्वरों और विरोधी खबरों को रोकने के लिए इस दस्तावेज में ज्यादा कठोर रास्ता अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन में रहने वाले विदेशी पत्रकारों और एनजीओ पर सख्ती की जाए, पश्चिमी संस्कृति के उत्पादों के चीनी बाजार में आने पर ज्यादा नियंत्रण रखा जाए और विरोधी विचारकों को विदेशी मीडिया में अपने विचार पेश करने से रोका जाए।"

अरुणाचल प्रदेश में चार चीनी नागरिक गिरफ्तार

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 27 जून)

अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले से चार चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जो बिना वैध दस्तावेज के भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें एक महिला भी है। ऊपरी सियांग जिले की सीमा उत्तर में तिब्बत से सटी हुई है। पुलिस का कहना है कि इन चीनी नागरिकों को 25 जून को एक सीमांत गांव पांगो से गिरफ्तार किया गया जहां मैकमोहन रेखा के करीब स्थित भारतीय गांव जोर्गिंग से तीन दिन पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। गौरतलब है कि चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी चीन के विशाल यू बंड से 70 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जोर्गिंग गांव से ही भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर तुतिंग थाना अध्यक्ष गेगांग जिजोंग दो पुलिस कर्मियों के साथ जोर्गिंग गए और उन्होंने चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों को शाम को थाने लाया गया। उनके नाम पता नहीं चल पाए हैं। तुतिंग यिंगकियोंग के विधायक आलो लिबांग ने बताया कि ये चीनी नागरिक करीब 18 दिन पैदल चलकर भारतीय गांव में पहुंचे हैं। लिबांग ने बताया कि उनके आने का उद्देश्य नहीं पता चल पाया है, लेकिन पुलिस, सेना, एसएसबी, आईटीपीबी और एसआईबी की संयुक्त टीम उनसे पूछताछ कर रही है।

यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि चीनी नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया हो जिसे बीजिंग लगातार अपना क्षेत्र होने का दावा करता रहता है। पिछले साल मई में अरुणाचल प्रदेश के आंजवा जिले से 28 साल के एक चीनी नागरिक

गुआन लियांग को गिरफ्तार किया गया था। लियांग भी बिना वैध दस्तावेज के भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था।

नेपाल में चीन को सामरिक फायदा

(विजय सखूजा, जेम्सटाउन फाउंडेशन, 17 जून)

संविधान तैयार करने में नेपाल की अक्षमता की वजह से वहां जारी राजनीतिक संकट और नेपाल की मुख्यधारा राजनीति में माओवादियों के बड़े राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने से चीन के लिए इस बात के लिए आदर्श स्थिति बनी है कि वह नेपाल पर अपना प्रभाव और दबाव बढ़ा सके। चीन जिस तरह से नेपाली नेतृत्व पर दबाव बनाने में सक्षम हुआ है, नेपाल के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक विकास रणनीति में घुसपैठ कर चुका है और नेपाल में रहने वाले करीब 20,000 निर्वासित तिब्बतियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगा रहा है उससे भारत की चिंता बढ़ गई है। नेपाल तक अपनी ज्यादा पहुंच बनाकर चीन भारत के लिए उस सुविधा को सीमित कर रहा है जो भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से एक बफर देश के रूप में नेपाल मुहैया कराता रहा है। चीनी और नेपाली सेना ने बहुत सक्रिय सैन्य आदान–प्रदान कार्यक्रम चलाए हैं जिनमें साजो–सामान की आपूर्ति, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा विकास और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का आना–जाना शामिल है, जबकि भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और पहले वहां के शासकों का भारत के प्रति झुकाव रहा है। हाल के दिनों में नेपाली सेना को चीन से बहुत तरह के सैन्य साजो–सामान मिले हैं, जिनमें निर्माण एवं इंजीनियरिंग मशीनरी, गैर घातक उपकरण शामिल हैं। साल 2008 में चीन की जनमुक्ति सेना के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मा जियोशियन ने नेपाल को 26 लाख डॉलर की गैर घातक साजो–सामान सहायता देने की घोषणा की। इसी प्रकार साल 2009 में चीनी सेना ने नेपाल सेना को अस्पताल निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए 30 लाख डॉलर की सहायता दी। गत मार्च में अपने काठमांडू दौरे के अवसर पर चीनी जनमुक्ति सेना के अध्यक्ष जनरल छेन बिंगडे ने फिर 2 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की और यह भरोसा दिया कि आगे और भी सहयोग दिया जाएगा। हालांकि, चीन की क्षमता को देखते हुए यह सैन्य सहायता थोड़ी ही है, लेकिन भारत के लिहाल से यह काफी बड़ी बात है और इसके संकेत काफी गहरे हैं। साल 2008 में चीन और नेपाल ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) को नेपाल से रेलमार्ग से जोड़ने की घोषणा की थी। इसके तहत नेपाल के सीमावर्ती कस्बे खासा से तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक 770 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग का निर्माण किया जाना है। यह परियोजना साल 2013 तक पूरी होने की उम्मीद है। ल्हासा–खासा रेल नेटवर्क से नेपाल की क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत पर निर्भरता कम हो जाएगी। भारतीय बंदरगाहों तक संपर्क बेहतर न होने और इन बंदरगाहों की क्षमता कम होने की वजह से नेपाल को व्यापार और ईंधन आपूर्ति में काफी अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उसके आयातित माल काफी महंगे हो जाते हैं और निर्यात में काफी देरी होती है। चीन के अपनी दक्षिणी सीमा पर रेलमार्ग के विस्तार ने भारत के पेशानी पर बल डाल दिए हैं, खासकर सुरक्षा हलकों में इसे लेकर चिंता है क्योंकि उनका मानना है कि चीनी बुनियादी ढांचा नागरिक और सैन्य दोंनों तरह के उद्देश्यों को साधने के लिए बनाया जा रहा है। नेपाल और तिब्बत के बीच करीब 1400 किलोमीटर लंबी साझा सीमा है और इस सीमा पर करीब 34 बड़े पर्वतीय दर्रे पड़ते हैं। इन दर्रो से होकर ही दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए संपर्क मार्गों का विकास किया जा सकता है। तिब्बती शरणार्थी नेपाल होकर भारत के शहर धर्मशाला आते हैं ताकि वे अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के दर्शन कर सकें। पहले नेपाली पुलिस एवं सरकारी अधिकारी यूएनएचसीआर के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते थे कि तिब्बती शरणार्थी सुरक्षित रूप से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच सकें। साल 2008 में नेपाल में माओवादियों और कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक उभार से पहले यह व्यवस्था बदस्तूर जारी थी। लेकिन इसके बाद काठमांडू के स्वागत केंद्र में पंजीकृत होने वाले तिब्बती शरणार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। यह बात साफ हो गई है कि चीन सरकार नेपाल पर यह दबाव बनाने में कामयाब रही है कि वह तिब्बती शरणार्थियों द्वारा चलाई जा रही चीन विरोधी गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण करे।

कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल के भारत के साथ मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। वास्तव में भारत का वहां प्रभाव इतना गहरा है कि काठमांडू के पशुपति नाथ मंदिर में दैनिक पूजा भारतीय पुजारियों द्वारा की जाती है। इसके अलावा बहुत से नेपाली नागरिकों की भारत में रिश्तेदारी है, भारत के गोरखा बटालियन में हजारों की संख्या में नेपाली नागरिक काम कर रहे हैं। चीन इस बात से वाकिफ है कि भारत का नेपाल पर गहरा सांस्कृतिक प्रभाव है इसलिए उसने इसे हल्का करने के लिए शुरू किए हैं। नेपाली जनता के बीच चीनी संस्कृति और भाषा के प्रसार के लिए नेपाल में कई चीनी अध्ययन केंद्र (सीएससी) खोले गए हैं। दक्षिणी नेपाल के भारतीय सीमा से सटे इलाकों में 33 सीएससी खोले गए हैं। साल 2007 में चीन ने काठमांडू विश्वविद्यालय में कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोला है जहां करीब 1000 नेपाली विद्यार्थी चीनी भाषा सीखते

इस बात की भी चिंता है कि चीन इन सीएससी को नेपाल में भारतीय गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए 'जासूसी केंद्र' के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जनवरी 2011 में भारत–नेपाल सीमा पर तैनात भारत के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसने वाले तीन चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की

1 कैनबरा (आस्ट्रेलिया) में 14 जून, 2011 को तिब्बत पर सर्वदलीय संसदी
स्टीवार्ट–डलियल
2 कैनबरा (आस्ट्रेलिया) में 14 जून, 2011 को विपक्ष के नेता एवं सांसद श्री
3 बढ़ती खाद्य कीमतों से चीन में नागरिक अशांति की आशंका बन गई है।
4 चीन द्वारा 1959 में तिब्बत पर कब्जे के बाद भारत और चीन की सीमा
1962 का रक्तरंजित युद्ध हुआ। फोटोः एपी
5 परमश्रेष्ठ 13वें सोना गोंत्से रिनपोछे
6 धर्मशाला के गांगछेन किशांग में 2 जून, 2011 को नवनिर्मित कशग सचि
7 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेशी मामलों की समिति के सामने तिब्बत
8 (बाएं से दाएं) सीटीए के श्री तेनजिन नोर्बू, कतुद्दिसा संघ थाइलैंड के श्
अंतरराष्ट्रीय तिब्बत नेटवर्क के श्री सेरिंग छोडुप।
9 फ्रांस की सीनेट में 8 जून, 2011 को सीनेटरों और पत्रकारों को संबोधित
दूसरे) श्री केलसांग ग्यालत्सेन।
10 तिब्बत के कार्डजे में तिब्बतियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के सम
जुलूस निकाला।

(9)

(8)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

आंख से

य समूह के सदस्यों के साथ परमपावन दलाई लामा। फोटोः रुस्टी

ो टोनी एबॉट के साथ परमपावन दलाई लामा। फोटोः रुस्टी स्टीवार्ट–डलियल

पहली बार एक–दूसरे के पास हो गई। इसके तीन साल बाद भारत–चीन में

वालय का उद्घाटन करते परमपावन दलाई लामा।
पर बोलते रिचर्ड गेरे। फोटोः पॉलिटिको
श्री कोमैन सूंग, जापान के सुपर संघ के सचिव वेन. शुनतेत्सु इजियामा और

करते परमपावन दलाई लामा के दूत और फ्रांस के सक्रिय प्रतिनिधि (बाएं से

र्थन में धर्मशाला में तिब्बती भिक्षुओं ने वियतनाम के मित्रों के साथ मोमबत्ती

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

(7)

(6)

सीमा पर बनने वाले 5,500 से ज्यादा 'स्थायी चौकियों और बंकर' का निर्माण तेज कर दिया गया है ताकि उनका काम चार–पांच साल में पूरा हो सके। इनका निर्माण पूर्वी सेना कमान के लिए गठित सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा मंजूर 9,243 करोड़ रुपए की सैन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है।

हैं। दूसरी तरफ, चीन और नेपाल के पर्यटन मंत्रालय भी इस बात के लिए गहराई से प्रयास कर रहे हैं कि चीनी पर्यटकों की वीजा फीस घटाकर नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा चीनी युआन को पर्यटकों और कारोबारियों के लिए परिवर्तनीय बनाया गया है। जून, 2010 में चाइना रेडियो इंटरनेशनल ने काठमांडू में अपनी एक शाखा खोली और चीनी भाषा सिखाने के लिए नेपाली सेवा शुरू की। भारत में इन घटनाओं को इस तरह से ही देखा जा रहा है कि नेपाल में चीन भारत के असर को कम करने का प्रयास कर रहा है। इस बात की भी चिंता है कि चीन इन सीएससी को नेपाल में भारतीय गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए 'जासूसी केंद्र' के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जनवरी 2011 में भारत–नेपाल सीमा पर तैनात भारत के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसने वाले तीन चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया।

पूछताछ के दौरान चीनी नागरिकों ने बताया कि वे नेपाल में काम करने वाले इंजीनियर हैं। एक एसएसबी अधिकारी ने कहा, "प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लगता है कि वे भारत में जासूसी करने आए हैं। चीन नेपाल पर अपनी सामरिक प्रभुत्व जमाए रखने के लिए सख्त और नरम हर तरह के रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने नेपाली नेतृत्व से यह वचन लिया है कि नेपाल में रह रहे तिब्बतियों शरणार्थियों को चीन–विरोधी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह बात ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण है जब पूरी दुनिया में तिब्बत को आज़ाद करने का आंदोलन जोर पकड़ रहा है और खासकर तिब्बतियों के प्रति मानवाधिकार संबंधी मसलों को लेकर चीन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि चीन ने नेपाल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास और नेपाल में रहने वाली जनता तक आर्थिक विकास की किरण पहुंचाने का प्रयास करके वहां परंपरागत भारतीय प्रभाव को कम करने की कोशिश की है। इससे चीन का भारी सामरिक एवं आर्थिक फायदा हुआ है और नेपाल में अपने कब्जे में लेने का अवसर मिला है। तीसरी बात यह है कि चीन द्वारा नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास से भारत के लिए और दबाव की बात है और इससे भारत की अधीरता बढ़ रही है। अब भारत के खिलाफ लड़ाई के समय पीएलए के लिए अपने सैनिकों को तत्काल भारतीय सीमा तक भेजना संभव हो गया है। अंत में यह कह सकते हैं कि नेपाल के साथ भारत के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों के बावजूद चीन उसको भारतीय असर से दूर करने में सक्षम हुआ है।

(लेखक विजय सखूजा नई दिल्ली के इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में निदेशक (रिसर्च) हैं)

चीन तिब्बत को भविष्य के युद्ध क्षेत्र में बदल रहा है

(डेक्कन हेराल्ड, 2 जून)

तिब्बत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से भारत सरकार की चिंता बढ़ गई है। रक्षा मंत्री ए. के. एंटोनी ने संसद को बताया है कि चीन सरकार तिब्बत में तेजी से रेल, सड़क, एयरपोर्ट, दूरसंचार ढांचे और सैन्य शिविरों का निर्माण कर रही है। चीन की सुरक्षा के लिहाज से तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन की कुल जमीन का करीब एक–चौथाई हिस्सा तिब्बत में ही है। तिब्बत पर नियंत्रण चीन की राष्ट्रीय एकता की व्यापक अवधारणा का हिस्सा है जिसे राष्ट्रपति हू चिन पाओ, "चीनी विशेषताओं और तिब्बती महक के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ना" कहते हैं। तिब्बत में साल 2008 में हुए व्यापक प्रदर्शनों को देखते हुए इस इलाके में अर्द्ध सैनिक बलों, चीनी सीमा गार्ड और रक्षक सेनाओं की संख्या बढ़ा दी गई है।

तिब्बत में बुनियादी ढांचे के केंद्रित विस्तार ने जन मुक्ति सेना (पीएलए) को यह ताकत दी है कि वह तेजी से कहीं भी अपनी टुकड़ियों को भेज सके। तिब्बत की सड़कें सेना की जरूरतों के मुताबिक बनाई जा रही हैं ताकि युद्ध या आंतरिक अशांति के दौरान पीएलए को इसका फायदा मिल सके। खासकर भारत के पूर्वी सीमा के पास चीन द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास चिंताजनक है क्योंकि इससे पीएलए वहां मुख्यभूमि से बहुत कम समय में पहुंच सकती है। टीएआर के आसपास नई हवाई पट्टियों का निर्माण, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) और हेलीपैड में सुधार के साथ नए परिवहन विमान खरीदने से चीन की सामरिक वायु वहन क्षमता काफी बढ़ गई है जिसकी वजह से वह बहुत कम समय में अपनी सेनाओं को कही भी भेज सकता है।

एक और बड़ा बुनियादी ढांचा विकास तिब्बत में नए मिसाइल अड्डे का निर्माण करना है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने भारत से सटी सीमा पर उन्नत डोंग फेंग–21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किए हैं। भविष्य में यदि कभी भारत से लड़ाई होती है तो पीएलए आसानी से ताइवान सीमा से उठाकर 500 से 600 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भारतीय सीमा पर तैनात कर सकता है। तिब्बत भू–भाग की भौगोलिक जटिलता, विषम जलवायु आदि की वजह से चीन के अभियान पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस पहलू के समाधान के लिए पीएलए ऐसे हाइपरबैरिक चैम्बर का निर्माण कर रही है जिससे अन्य जगहों की सैन्य टुकड़ियां तिब्बत की दशा से अभ्यस्त हो सकें। वह करीब 4500 मीटर अक्षांश पर टीएआर के नागछू सैन्य सब कमांड में तैनात टुकड़ियों के लिए पहली

बार ऑक्सीजन से समृद्ध बैरक का भी निर्माण कर रही है।

इसलिए अब यह भारत के भी हित में है कि तिब्बत से सटी सीमा पर बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए ताकि भविष्य में लड़ाई कि किसी स्थिति के आने पर चीनी खतरे से निपटने के लिए इन इलाकों में तेजी से अपनी सेनाओं को भेजने में आसानी हो। इसी के साथ भारत को अपनी खुफिया, निगरानी और टोही (आईएसआर) क्षमता भी बढ़ानी होगी ताकि सीमा पर लगातार चौकसी रखी जा सके। सेना और वायुसेना को अपनी मारक क्षमता भी बढ़ानी होगी कि ताकि काफी दूरी से ही पीएलए की टुकड़ियों को नेस्तनाबूद किया जा सके। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि प्रभावी प्रतिरक्षा कभी भी सस्ते में नहीं हो सकती।

पीएलए की निगरानी के लिए चीन सीमा पर भारत ने बढ़ाई चौकसी

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 जून)

भारत अब चीन सीमा पर जासूसी ड्रोन या यूएवी (बिना मानव चालित वायु यान) और हल्के निगरानी हेलीकॉप्टर तैनात कर रहा है ताकि चीन की जनमुक्ति सेना (पीएलए) की बढ़ी हुई गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

सीमा पर बनने वाले 5,500 से ज्यादा 'स्थायी चौकियों और बंकर' का निर्माण तेज कर दिया गया है ताकि उनका काम चार–पांच साल में पूरा हो सके। इनका निर्माण पूर्वी सेना कमान के लिए गठित सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा मंजूर 9,243 करोड़ रुपए की सैन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया, "सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू विमानों को भारतीय वायु सेना के तेजपुर और छाबुआ में तैनात कर दिया गया है। असम में स्थित सेना के विमानन बेस को भी उन्नत किया जा रहा है और सात हेलीकॉप्टर के साथ वहां चार इजराइली सर्चर–2 यूवए की तैनाती कर दी गई है।"

सेना दो नए पर्वतीय पैदल सेना डिवीजन बनाने के बाद अब एक पर्वतीय हमलावर कॉर्प्स के गठन पर जोर दे रही है। दोनों पर्वतीय डिविजनों के मुख्यालय क्रमशः नगालैंड के जकामा और असम के मिसामारी में हैं और इनमें 1,260 अधिकारियों और 35,011 सैनिकों की तैनाती की गई है। हालांकि यह योजनाएं थोड़ी देर से शुरू हुई हैं, लेकिन यह सब चीन के उस भारी सैन्य बुनियादी ढांचा निर्माण के सामरिक जवाब के तहत ही है जो पिछले दो दशकों से चीन 4,057 किलोमीटर लंबी नियंत्रणरेखा के उस पार तैयार कर रहा है। चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपना दखल तेजी से बढ़ा रहा है। इस इलाके में भारत को लक्षित कर हुए चीन–इस्लामाबाद गठजोड़ ने भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की चिंता बढा दी है। हालांकि इस इलाके में भारत की तैयारी ढीली ही लग रही है। नियंत्रण रेखा पर सभी मौसम में चलने लायक करीब 73 सड़कें बनाए जाने की भारत की योजना है लेकिन इनमें से भी तक 15 सड़कें ही तैयार हो पाई हैं।

आईटीबीपी पर संचालन नियंत्रण चाहती है भारतीय सेना

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 जून)

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी सैनिकों की बढ़ती सक्रियता के बीच भारतीय सेना यह चाहती है कि सीमा के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) पर उसका 'संचालनात्मक नियंत्रण' हो। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सेना का कहना है कि चीन की जनमुक्ति सेना के आक्रामक रुख को देखते हुए भारत के सीमा प्रबंधन के लिए 'संबद्धता, समन्वय और सिनर्जी' बहुत जरूरी है और इसके लिए यह जरूरी है कि आईटीबीपी को उसके अधिकार क्षेत्र में रखा जाए।

सेना का मानना है कि इस तरह के कदम से संचालनात्मतक उत्पादकता बढ़ेगी और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि खासकर पूर्वी लद्दाख में संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो जहां आईटीबीपी तैनात है। आईटीबीपी गृह मंत्रालय के तहत आने वाले सात केंद्रीय पुलिस बलों में से एक है जिसको एलएसी के 826 किलोमीटर हिस्स्से के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है।

सेना एलएसी के इस हिस्से में भी व्यापक रूप से मौजूद है, लेकिन वह आईटीबीपी पर संचालन नियंत्रण तब ही हासिल कर पाती है, जब युद्ध की कोई स्थिति आ जाए। समूचे 4,057 किलोमीटर लंबे एलएसी पर 'एक बिंदु नियंत्रण' और 'बॉर्डर पुलिसिंग' की जगह प्रभावी 'सीमा सुरक्षा' के लिए सेना पहले भी कई बार आईटीबीपी को अपने अधिकार में देने की मांग करती रही है। रक्षा मंत्रालय ने छह साल पहले भी सेना के इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदि के पास भेजा था पर इस पर कुछ नहीं हो पाया। रोचक बात यह है कि तब इस प्रस्ताव का मुख्य विरोध विदेश मंत्रालय की तरफ से आया था जिसका मानना था कि इससे बेवजह चीन भड़क जाएगा। लेकिन चीन के पास ऐसा करने की नैतिक वजह नहीं है। वह लगातार एलएसी के तीनों सेक्टर–पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (उत्तराखंड, हिमाचल) और पूर्वी (सिक्किम, अरुणाचल) में सैनिकों की घुसपैठ की नीति चला रहा है। आधिकारिक रूप से अक्सर चीन इन घुसपैठ को बहुत हल्के में लेता

"किसी भी देश के साथ जल साझेदारी समझौता करने से इनकार करने पर चीन कभी भी क्षमायाचक नहीं रहा है। चीन हमेशा यह कहता रहा है कि वह निचले तटों पर स्थित देशों का ध्यान रखेगा, लेकिन दुनिया के विशाल बांधों की करीब आधी संख्या चीन में ही है।

"चीन लगातार अपनी परियोजनाओं का आकार बढ़ाता जा रहा है। उन्होंने मेकांग में भी ऐसा किया है।"

है और यह कहता है कि यह अनसुलझे एलएसी को लेकर 'धारणाओं में अंतर' की वजह से भी हो जाता है। लेकिन सच यह है कि चीन पिछले कई साल से आक्रामक सीमा निगरानी में लगा हुआ है ताकि विवादित क्षेत्रों पर अपना दावा मजबूत कर सके और भारत पर दबाव बना सके। पिछले सालों में भारत की समूची सीमा प्रबंधन नीति काफी हद तक ढुलमुल ही रही है, जबकि इसकी 14,880 किलोमीटर लंबी सीमा 17 राज्यों से गुजरती है और छह देशों को छूती है। इसके अलावा मुंबई में समुद्री रास्ते से हमले के बाद सरकार को देश की 5,422 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा और 1,197 किलोमीटर लंबी द्वीपों की सीमा सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। चीन एवं पाकिस्तान और म्यांमार, बांग्लादेश एवं नेपाल के साथ लंबी सीमा पर तैनात विभिन्न तरह के सुरक्षा बलों जैसे बीएसएफ, आईटीपीबी, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), असम राइफल्स और सेना के बीच समन्वय का लगातार अभाव रहा है जो अलग–अलग प्रमुखों और मंत्रालयों को रिपोर्ट करते हैं।

चीन द्वारा पड़ोसी देशों में बंदरगाह बनाने से भारत असहज

(एनपीआर, 20 जून)

हालांकि, दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि उनको यह उम्मीद नहीं है कि चीन रातोरात लोकतंत्र में बदल जाएगा।

चीन जैसे–जैसे आर्थिक एवं सैन्य ताकत बढ़ा रहा है एशिया के एक अन्य बड़े और तेजी से उभरते ताकत से उसका सामना हो रहा है। मध्य–पूर्व के ईंधनों और अफ्रीका के संसाधनों की भूख ने चीन को हिंद महासागर तक पहुंचाया है। भारत के कई प्रतिरक्षा विश्लेषक काफी असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि चीन भारत के कई पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक बंदरगाहों का विकास कर रहा है। भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग चीन की नई सैन्य और सामरिक रणनीति के बारे में सोचने पर काफी समय लगा रहे हैं।

रिटायर्ड वाइस एडमिरल अरुण कुमार सिंह ने बताया, "चीन चाहता है कि भारत असंतुलन की स्थिति में रहे क्योंकि वह चाहता है कि भारत दक्षिण एशिया तक ही सीमित रहे, जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।" एक नौ सैनिक रहे सिंह खासकर चीन द्वारा म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में वाणिज्यिक बंदरगाह बनाए जाने को लेकर चिंतित हैं जिसे 'मोतियों का धागा' रणनीति कहा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि चीन इन बंदरगाहों का निर्माण अभी तो वाणिज्यिक उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन भविष्य में इन्हें सैनिक अड्डों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नई दिल्ली के 'शांति एवं संघर्ष अध्ययन संस्थान' के वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता जैबिन जैकब ने कहा कि भारतीय नीति नियंताओं को इस बारे में ज्यादा चिंता दिखानी होगी कि चीन अपनी सेना का इस्तेमाल 'गैर युद्ध सैन्य संचालनों' में कर रहा है जैसे कि सोमालिया के तट पर लुटरों के खिलाफ अभियान में। उन्होंने कहा, "आप चीन जैसे एक ऐसे देश से कैसे निपट सकते हैं जो कि सक्रियता से हिंद महासागर के आर–पार जा रहा है और हिंद महासागर के तटीय देशों से अपने रिश्ते बना रहा है जिन पर परंपरागत रूप से भारत का प्रभाव रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत यदि अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है तो उसे इन छोटे पड़ोसी देशों और उनकी समस्याओं के साथ सक्रियता से जुड़ना पड़ेगा।

जल साझेदारी समझौते से चीन के इनकार से भारत पर होगा गंभीर असर

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 जून)

चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी की धारा को मोड़ने की हाल में जताई आशंका कोई ऐसा पहला अवसर नहीं है जब भारत ने अपने साम्यवादी पड़ोसी देश की जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में चिंता जताई हो और यह कोई अंतिम बात नहीं है। चीन न केवल ब्रह्मपुत्र पर 24 परियोजनाएं बना रहा है, बल्कि 2000 मेगावॉट क्षमता की पांच परियोजनाएं बामचू नदी पर भी बना रहा है जिसे भारत में कोसी कहते हैं। इन परियोजनाओं पर चिंता जताने वाला भारत अकेला देश नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की साझेदारी के किसी भी प्रस्ताव को चीन के न मानने से दक्षिण–पूर्व एशिया के अन्य देशों जैसे वियतनाम, कम्बोडिया, थाइलैंड और लाओस में भी डर का माहौल है जो कि मेकांग नदी के निचले तट पर स्थित हैं। चीन ने मेकांग नदी पर छह बड़े बांध बनाए हैं और तीन और बांध का काम चल रहा है। चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत की वजह से उस पर किसी तरह का अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं है और अब मेकांग के निचले तट पर स्थित देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है कि वे खुद ही अपनी रक्षा करें। चीन द्वारा विशाल बांधों के निर्माण से दक्षिण–एशिया में सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होगा क्योंकि यहां की अधिकांश नदियां तिब्बत से निकल कर आती हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन परियोजनाओं की अगर किसी भी तरह से सैटेलाइट से निगरानी की गई तो चीन जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा सकता है। ब्रह्मपुत्र पर झांगमू बांध बनाए जाने के पहले संकेत उपग्रह से हासिल चित्रों से ही मिले थे जिसके निर्माण की चीन पिछले साल पुष्टि कर चुका है।

सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी कहते हैं, "किसी भी देश के साथ जल साझेदारी समझौता करने से इनकार करने पर चीन कभी भी क्षमायाचक नहीं रहा है। चीन हमेशा यह कहता रहा है कि वह निचले तटों पर स्थित देशों का ध्यान रखेगा, लेकिन दुनिया के विशाल बांधों की करीब आधी संख्या चीन में ही है।

भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा क्योंकि यहां की अधिकांश नदियां तिब्बत से ही निकलती हैं। इस मसले को जल संसाधन मंत्रालय बहुत हल्के में लेता है और इसके लिए चीन पर कभी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं बनाया गया जबकि चीन के इन कदमों से प्रभावित होने वालों में रूस, कजाकिस्तान, म्यांमार, थाइलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस जैसे देश शामिल हैं।"

संयोग से इन परियोजनाओं के बारे में अब कुछ भी छिपा नहीं है। इनमें से ज्यादातर की जानकारी परियोजना निर्माण में लगी कंपनियों ने सार्वजनिक की है। चीन सरकार द्वारा बामछू नदी पर कैंगगांग, क्युडांग, सांगडांगला, शाली और लक्सियांग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चीन हमेशा से ही यह कहता रहा है कि इन पर बन रही परियोजनाएं जल संग्रहण की नहीं हैं बल्कि नदी के प्रवाह के साथ ही संचालित होती हैं। लेकिन चेलानी का कहना है कि भारत को इस बात पर गहरी नजर रखनी होगी कि मेकांग में क्या हो रहा है जहां कई परियोजनाएं 6000 से 8000 मेगावॉट क्षमता की हैं। दूसरी तरफ भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना सिर्फ 1500 मेगावॉट की है। चेलानी ने कहा, "चीन लगातार अपनी परियोजनाओं का आकार बढ़ाता जा रहा है। उन्होंने मेकांग में भी ऐसा किया है।" समस्या सिर्फ बांधों की ही नहीं है। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के पूर्व सदस्य और जलवायु परिवर्तन पर एशियाई विकास बैंक के सलाहकार एस. के. शर्मा ने बताया, "निचले तटीय देशों के लिए चीन चाहे तो जल के स्वभाव को भी बदल सकता है जिसका भारत और नेपाल पर गहरा असर होगा। नदियों में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है खासकर इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि इस क्षेत्र के देशों में जल साझेदारी का कोई समझौता नहीं हुआ है।"

तेरहवें दलाई लामा का ऐतिहासिक मकान ढहाया गया

(आरएफए, 15 जून)

चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के 13वें दलाई लामा के करीब एक शताब्दी पुराने लांगदुन पारिवारिक आवास को ढहा दिया है। इस विरासत स्थल को बचाने की तमाम अपील को ठुकराते हुए चीनी अधिकारियों ने इस नेस्तनाबूद कर दिया। लांगदुन परिवार से जुड़े एक तिब्बती सूत्र ने यह जानकारी दी है। मौजूदा दलाई लामा के पहले दलाई लामा रहे थुपतेन ग्यात्सो का मकान तिब्बत की राजधानी ल्हासा के दक्षिण में किछु नदी के पास था। इस मकान को गिराने की शुरुआत 10 जून से हुई। तिब्बतियों द्वारा 'महान 13वें' से संबोधित किए जाने वाले 13वें दलाई लामा का जन्म दक्षिणी तिब्बत के धाकपो में एक खेतिहर दंपती के यहां हुआ था। सूत्रों ने बताया, "लांगदुन परिवार के सदस्यों ने ल्हासा शहर प्रशासन से अनुरोध किया था कि वे इस मकान को न गिराएं, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। तिब्बत पर 13वें दलाई लामा के शासन के समय में ही 1904 में ब्रिटिश सैनिकों ने और 1909–10 में चीनी सैनिकों ने चढ़ाई की थी, लेकिन इन दोनों हमलों से बच जाने की वजह से उनका प्रभाव काफी बढ़ गया था। उन्होंने बाद में इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि तिब्बत पर चीन फिर 1950 में हमला करेगा और दिसंबर 1933 में 57 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। उन्होंने तिब्बत की सेना के आधुनिकीकरण प्रयास शुरू किए।

हैकरों ने उनके मेल सेटिंग को भी बदल दिया।

चीनी लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम होगा पारदर्शिताः दलाई लामा

(टिबेट डॉट नेट, 13 जून)

परमपावन दलाई लामा ने कहा है कि पारदर्शी सरकार और प्रेस को आज़ादी चीन के लिए लोकतंत्र की ओर बढ़ने के प्रारंभिक कदम होंगे। आस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में चीनी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए 12 जून को परमपावन ने यह बात कही। परमपावन आस्ट्रेलिया में अपने 11 दिन के दौरे के दौरान मेलबर्न में चीनी युवाओं, बौद्धों और लोकतांत्रिक आंदोलनकारियों से मिले। इनमें से बहुत से लोग मेलबर्न के चीनी–तिब्बती मैत्री समूह से जुड़े थे जिसकी स्थापना का सुझाव परमपावन दलाई लामा ने अपने पिछले दौरे पर दिया था। परमपावन ने चीनी समूह को बताया कि वह चीन सरकार को यह दिखाने में गर्व महसूस करेंगे कि उन्होंने निर्वासित तिब्बतियों के बीच वास्तविक लोकतंत्र कायम करने में किस तरह से सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि अब यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का दायित्व बनता है कि 60 साल तक सत्ता में रहने के बाद अपने को रिटायर करे। हालांकि, दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि उनको यह उम्मीद नहीं है कि चीन रातोरात लोकतंत्र में बदल जाएगा। उन्होंने कहा, "चीन एक बड़ा देश है और वहां लोकतंत्र नहीं है। उसका इस रास्ते पर धीरे–धीरे आगे बढ़ना सही होगा। सबसे पहला कदम यह होगा कि वह ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा खुला हो। उसे इसकी शुरुआत प्रेस को आज़ादी देने और गलत सूचनाओं का प्रसार रोक कर करना चाहिए।

"हमें अक्सर चीनी सैनिकों से धमकी मिलती है, जबकि हमारी सरकार स्थानीय छांगपा जनजाति के चरवाहों को नियंत्रण रेखा पर अपनी भेड़ों को चराने की इजाजत भी नहीं देती।"

चीन में दो वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों का जी–मेल खाता हैक किया गया

(हिंदुस्तान टाइम्स, 4 जून)

बीजिंग में तैनात दो वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों का

इन बदलावों का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में चल रहा तिब्बत की आज़ादी का संघर्ष लगातार चलता रहे।

जी–मेल एकाउंट हैक कर लिया गया था। कई अन्य राजनयिकों ने भी यह संदेह जताया है कि उनके मेल एकाउंट को निशाना बनाया जा रहा है। चीन में तैनात इन राजनयिकों का कहना है कि पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हैकरों ने इन राजनयिकों के मेल एकाउंट में घुसपैठ की, पासवर्ड बदल दिया और उनके मेल से कई मेल फारवर्ड कर लिए। हैकरों ने उनके मेल सेटिंग को भी बदल दिया। गूगल ने भी यह स्वीकार किया है कि उसके सैकड़ों ई–मेल यूजर चीनी हैकरों के निशाने पर है। हैकरों के निशाने पर कई सरकारी अधिकारी, सेना कमी, नेता और पत्रकार हैं। हाल में अमेरिकी सरकार ने कहा था कि वह साइबर हमलों जैसे ई–मेल एकाउंट हैक करने को भी 'युद्ध की कार्रवाई' के तहत वर्गीकृत करेगी और गूगल–चीन के बीच चल रहे झड़प से चीन–अमेरिकी रिश्तों में भी तनाव बढ़ेगा। नाम न छापने की शर्त पर एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि हैकरों ने एक ई–मेल भी भेजा था जिसमें एक 'मालवेयर' था। मालवेयर एक संदिग्ध सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को गड़बड़ा सकता है और एंटी वायरस सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। उन्होंने बताया, "ऐसी भी खबरें हैं कि हैंकरों ने ई–मेल सेटिंग भी बदल दी ताकि वे जिस ई–मेल पते पर भी चाहें मेल को फॉरवर्ड कर दें।"

चीन ने नेपाल में नई पारी शुरू की

यह निश्चित रूप से एक ऐसी पहल है जो तिब्बती नेतृत्व की ताकत, आत्मविश्वास, दृढ़ता और साधन संपन्नता को प्रदर्शित करती है।

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 जून)

चीन के नेपाल में नए राजदूत यांग हुलान के काठमांडू पहुंचने के साथ ही यह अटकलें शुरू हो गईं कि नेपाल में चीन नई पारी शुरू कर रहा है और उसे चीनी विदेशी मामलों के तहत एक प्राथमिकता वाले देश में रखा गया है।

इसके पहले कोरिया प्रायद्वीप के मामलों के विशेष दूत रहे यांग क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और नेपाल भेजे जाने वाले सबसे वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनके तीन पूर्व राजदूतों सुन हेपिंग, झेन जियांगलिन और कियु गुओहांग के समय में नेपाल में तिब्बती प्रदर्शनकारियों का चीन विरोधी प्रदर्शन बढ़ा है और वे इनको रोक नहीं पाए, नेपाल सरकार से तमाम अनुरोध के बावजूद कि वह इन प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटे। भारत ने भी विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव (सार्वजनिक राजनय) जयंत प्रसाद को नेपाल का नया राजदूत बनाया है।

डेमछोक में चीन कर रहा निर्माण, भारत ने लगाई रोक

(द ट्रिब्यून, 27 जून)

पूर्वी लद्दाख के विवादास्पद क्षेत्र डेमछोक ने भारत सरकार ने किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इससे स्थानीय नागरिकों में काफी गुस्सा हैं। लोगों का कहना है कि इस इलाके में सीमा पार चीन तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, लेकिन भारत सरकार मूकदर्शक बन कर देख रही है। चीन ने दक्षिण–पूर्वी लद्दाख के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र डेमछोक के पास अपनी सीमा में सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण तेज कर दिया है, लेकिन इसके मुकाबले भारत के कदम बचकाना ही हैं। भारत ने डेमछोक में स्थानीय निवासियों के किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि डेमछोक में चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और उनके द्वारा किए जा रहे निर्माण को रोका जा रहा है। लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद में निर्वाचित पार्षद गुरमे दोरजी ने बताया, "चीन अपनी तरफ बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है, इसलिए हम पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता।" दोरजी इसी इलाके में रहते हैं। दोरजी ने कहा कि इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार को कई बार लिखित याचिका भेजी है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला है। लद्दाख के न्योमा ब्लॉक के तहत आने वाले डेमछोक की आबादी करीब 7000 की है। यहीं से भारत–चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा गुजरती है। दिसंबर, 2009 में चीन ने डेमछोक में सड़क निर्माण पर भारत सरकार से आपत्ति जताई थी। स्थानीय नागरिकों के अनुसार चीन अपनी तरफ बड़ी–बड़ी नीली छत वाली सभी मौसम के अनुकूल इमारतें बना रहा है जिनमें 100 से 125 सैनिक आराम से रह सकते हैं। ट्रिब्यून अखबार को कई ऐसी तस्वीरें भी मिली हैं जिनमें चीनी सैनिकों ने लाल बैनर दिखाते हुए भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी हैं। इन बैनरों पर लिखा रहता है, "यह वास्तविक नियंत्रण रेखा है और आप चीनी क्षेत्र में हो।"

दोरजी ने बताया, "हमें अक्सर चीनी सैनिकों से धमकी मिलती है, जबकि हमारी सरकार स्थानीय छांगपा जनजाति के चरवाहों को नियंत्रण रेखा पर अपनी भेड़ों को चराने की इजाजत भी नहीं देती।"

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की वैधानिकता एवं भूमिका

केलसांग ग्याल्तसेन, परमपावन दलाई लामा के दूत

(द टिबेट पोस्ट डॉट कॉम, 21 जून, 2011, धर्मशाला)

एक बार फिर निर्वासित तिब्बतियों की छोटी सी दुनिया में इस बात को लेकर भावनात्मक और राजनीतिक बहसों के बवंडर में फंसी दिखती है कि

परमपावन दलाई लामा अपने प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकार तिब्बती प्रशासन के चुने हुए अंग को सौंपने जा रहे हैं और इस बात पर भी कि तिब्बती भाषा में ''निर्वासित तिब्बती सरकार'' को अब ''केंद्रीय तिब्बती प्रशासन'' ही कहा जाए। कई बार इस बहस का स्वर सताने वाला, कड़वा और अपने को पीड़ा पहुंचाने वाला हो जाता है जो बहस करने वाले कुछ तिब्बतियों के अपनी बात को साबित करने के लिए किसी हद तक जाने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है।

इस तरीके से अभी तक जो तर्क–वितर्क चल रहा है वह कुछ हद तक खुद को नुकसान पहुंचाने वाला और हतोत्साहित करने वाला है बजाए इसके कि इसमें जुड़े मसले को स्पष्ट करने में मदद मिले और अच्छी तरह से समझा जा सके। इन बदलावों का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व में चल रहा तिब्बत की आज़ादी का संघर्ष लगातार चलता रहे। ये बदलाव तिब्बती नेतृत्व की इस राजनीतिक इच्छाशक्ति और दृढ़ता को प्रदर्शित करते हैं कि तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई को तब तक जारी रखा जाए जब तक वह इस तरह से जमीन पर मजबूती से खड़ा नहीं हो जाता कि भविष्य में भाग्य के फेर से कैसा भी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण हो, वह कार्य करता रहे और जारी रहे। परमपावन दलाई लामा द्वारा अपनी राजनीतिक सत्ता केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के चुने हुए नेताओं को सौंपने को इस रूप में ही देखना और समझना चाहिए उनको तिब्बतियों की राजनीतिक परिपक्वता और तिब्बती जनता की दृढ़ता पर भरोसा है, खासकर तिब्बत के भीतर और निर्वासन में रहने वाली युवा पीढ़ी पर। मेरा मानना है कि यही वह केंद्रीय संदेश है जो इस बदलाव में निहित है और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तिब्बतियों, चीनी नेतृत्व तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को देना चाहता है।

यह निश्चित रूप से एक ऐसी पहल है जो तिब्बती नेतृत्व की ताकत, आत्मविश्वास, दृढ़ता और साधन संपन्नता को प्रदर्शित करती है। दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति प्रतिबद्धता की यह भावना निर्वासित तिब्बतियों के चार्टर में किए गए संशोधनों से साफ तौर पर जाहिर होती है। इन संशोधनों से यह साफ है कि परमपावन वह सब कुछ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और खासकर उसके लोकतांत्रिक नेतृत्व को सौंप देंगे जो शक्तियां और जिम्मेदारियां पहले समूची तिब्बती जनता के प्रतिनिधित्व और उसकी सेवा के लिए उनके और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को संयुक्त रूप से हासिल थीं। चार्टर की नई प्रस्तावना में रेखांकित किया गया है, "समूची तिब्बती जनता के प्रतिनिधि और वैधानिक शासन निकाय के रूप में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की भूमिका को सुरक्षित रखा जाएगा।"

इसमें इस बात को भी प्रतिस्थापित किया गया है कि दूसरी ईसा पूर्व से लेकर 1951 में तब तक तिब्बत एक संप्रभु राष्ट्र रहा है जब तक इस पर चीन जनवादी गणतंत्र ने हमला नहीं किया था। इसमें साल 1959 में निर्वासन में भारत आने के बाद परमपावन दलाई द्वारा कई राजनीतिक सुधार प्रयासों को भी रेखांकित किया गया है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने हाल में हुए बदलावों की वजह से समूची तिब्बती जनता के प्रतिनिधित्व का जनादेश खो दिया है। इसके विपरीत सच यह है कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने से राजनीतिक एवं कानूनी रूप से तिब्बत जनता के प्रतिनिधित्व की केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की वैधानिकता और मजबूत हुई है। प्रभुसत्ता तिब्बत की जनता में निहित है। इसका परिणाम यह होगा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जितनी परिपूर्ण तिब्बती सत्ता स्थापित की जाएगी तिब्बती जनता की आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व की उसकी वैधानिकता उतनी ही ज्यादा होगी। साल 1959 में भारत में निर्वासन में आने से पहले परमपावन दलाई लामा ने यह कहा था कि वह और उनका कशग (मंत्रिमंडल) जहां कहीं भी रहेंगे तिब्बत की जनता उन्हें अपनी सरकार और सच्चा प्रतिनिधि मानती रहेगी। परमपावन ने अपने कशग के मार्गदर्शन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की स्थापना की थी ताकि वह सक्रियता से तिब्बत के आंदोलन को आगे बढ़ा सके, तिब्बत में हो रहे दुखद घटनाओं पर दुनिया का ध्यान आकृति करें और तिब्बती जनता की रक्षा और भारत पहुंचने वाले 80,000 निर्वासित तिब्बतियों की देखभाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद ले सकें।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का आधिकारिक नाम "परमपावन दलाई लामा का केंद्रीय तिब्बती प्रशासन" है। हमारे आधिकारिक लेटर–हेड और मुहर पर यह विवरण प्रदर्शित है। अपने सभी विदेशी संबंधों में हम अपने को परमपावन दलाई लामा के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के रूप में ही परिचित कराते हैं। हम "निर्वासित तिब्बती सरकार" के रूप में कानूनी या राजनीतिक मान्यता नहीं चाहते क्योंकि हमे भरोसा है कि तिब्बती जनता परमपावन और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को अपनी सरकार और सच्चा प्रतिनिधि मानती है और यह लगातार हमारी वैधानिकता का स्रोत बना रहा है। हमारे निर्वासन की शुरुआत के समय से ही ऐसा लगता रहा है कि परमपावन के लिए यह बात साफ करना बेहद महत्वपूर्ण है कि वह अपने और अपने प्रशासन के लिए सत्ता या शासन में हिस्सेदारी का कोई दावा नहीं करते। हमारे निर्वासन का हमेशा ही यह प्राथमिक लक्ष्य रहा है कि तिब्बतियों को न्याय

तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बती केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन वे कई तरीकों से अपना समर्थन और जुड़ाव प्रदर्शित करते रहे हैं, जबकि ऐसा करने में उन्हें गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है।

सबसे पहले इन सबसे चीन का यह दुष्प्रचार बेकार साबित होगा कि तिब्बती नेतृत्व 'अलगाववाद' में लगा है और उनका यह दावा भी खोखला साबित होगा कि दलाई लामा "सामंती धर्मतंत्र" को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं।

मिले और तिब्बती जनता में बुनियादी मानवाधिकारों और आज़ादी की बहाली की जाए।

इस तथ्य के बारे में कोई गंभीर विवाद नहीं है कि तिब्बत की जनता केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तब तक अपनी वास्तविक सत्ता मानती रहेगी जब तक उसे परमपावन दलाई लामा का आशीर्वाद और पूरा समर्थन मिलता रहेगा, हाल के बदलावों के बावजूद। यह केवल तिब्बत की जनता ही तय कर सकती है कि वह अपना सच्चा प्रतिनिधि किसे मानती और स्वीकार करती है। हालांकि, तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बती केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन वे कई तरीकों से अपना समर्थन और जुड़ाव प्रदर्शित करते रहे हैं, जबकि ऐसा करने में उन्हें गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है। यदि निर्वासन में रहने वाला कोई तिब्बती हाल में हुए बदलावों की वजह से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को एक गैर सरकारी संस्था मानने लगता है तो यह उसकी व्यक्तिगत सोच और अकेले का निर्णय है। थोड़े भी राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी वाला हर तिब्बती यह जानता है कि परमपावन का एक राजनीतिक सिद्धांत यह भी है कि हमेशा "सबसे अच्छे की उम्मीद करो और सबसे खराब के लिए तैयार रहो।"

परमपावन के इस बुद्धिमत्तापूर्ण रवैए से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पिछले दशकों में तिब्बती जनता और तिब्बत आंदोलन की जरूरतों की ठीक तरह से पूर्ति हुई है और इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। चीन में रुचि रखने वालों के लिए यह कोई नया समाचार नहीं है कि हाल के सालों में चीन सरकार यह बात प्रदर्शित करती रही है कि वह अपने तथाकथित "मुख्य राष्ट्रीय हित" की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी। चीन पर नजर रखने वालों को यह बात पता भी चल गई होगी कि ताइवान और तिब्बत पर अपने दावों जैसे "मुख्य हितों" की रक्षा के लिए चीनी नेतृत्व कुछ भी कर सकता है। चीन में केंद्रीय पार्टी स्कूल के रणनीतिकार गोंग ली का बयान आया है कि, "जहां तक ताइवान और तिब्बत का संबंध है बीजिंग को एक इंच जमीन भी नहीं छोड़नी चाहिए।" यह खुली हुई बात है कि अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए दूसरे देशों को मजबूर करने वाले राजनय का इस्तेमाल कर रहा है। कई अन्य बढ़ते मामलों और संकेतों के बीच चीन की मजबूर करने वाली कूटनीति का प्रभाव और इस्तेमाल हाल में नेपाल में हमारे देशवासियों के साथ वहां की सरकार की नीतियों से देखा जा सकता है। यह बात आम है कि चीन दुनिया में किसी भी सरकार से राजनयिक संबंध शुरू करने से पहले "एक चीन नीति" के सिद्धांत को मानने और उस पर बने रहने की पूर्व शर्त थोपता है। आगे की ओर देखना और भविष्य में आ सकने वाले किसी राजनीतिक बदलाव से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाना एक जिम्मेदार और समझदार राजनीतिक नेतृत्व का कार्य है।

चीन के तुष्टीकरण से दूर परमपावन दलाई लामा के इन प्रयासों से चीनी नेतृत्व के सामने कई चुनौतियां खड़ी होंगी। सबसे पहले इन सबसे चीन का यह दुष्प्रचार बेकार साबित होगा कि तिब्बती नेतृत्व 'अलगाववाद' में लगा है और उनका यह दावा भी खोखला साबित होगा कि दलाई लामा "सामंती धर्मतंत्र" को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। एक ज्यादा व्यावहारिक और ठोस राजनीतिक स्तर पर परमपावन दलाई लामा ने एक बार फिर सुस्पष्ट रूप से यह बात साफ कर दिया है कि उन्हें चीनी नेतृत्व से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।वह चीन–तिब्बत वार्ता में तिब्बती जनता के अधिकार और कल्याण को ही सामने रखते आए हैं। उन्होंने यह बात साफ की है कि जिस बुनियादी मसले का समाधान होना चाहिए वह यह है कि एक पूर्ण स्वायत्तता को भरोसे के साथ लागू किया जाए जिससे तिब्बती जनता अपनी बुद्धिमत्ता और जरूरतों के मुताबिक अपना शासन खुद चला सके।

अपनी राजनीतिक सत्ता को छोड़कर परमपावन ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि तिब्बत आंदोलन से उनका जुड़ाव कोई व्यक्तिगत अधिकार या राजनीतिक पद हासिल करने के लिए नहीं है, न ही वह निर्वासित तिब्बती प्रशासन में कोई हिस्सेदारी चाहते हैं। एक बार जब चीन से कोई संतोषजनक समझौता होता है तो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन भंग कर दिया जाएगा और तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों को तिब्बत के प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी दी जाएगी। चार्टर में संशोधन करने के बाद भी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्य राजनीतिक एजेंडा अपने विवश देश की मुक्त आवाज़ बन कर तिब्बत की जनता की सेवा करना और दुनिया भर में तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विपरीत हमारी तरह से बिना किसी संदेह के यह बात साफ है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तिब्बत पर शासन करने का अधिकार नहीं चाहता। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य इससे जरा भी कम या ज्यादा नहीं है कि तिब्बती जनता के ऐसे अधिकारों को हासिल करने के संघर्ष का नेतृत्व करें जिससे वे अपने मामलों पर निर्णय खुद ले सकें और हमारी जन्मभूमि ''बर्फ की धरती'' पर आज़ादी के साथ रह सकें। तिब्बती भाषा में हमारे प्रशासन के नाम को बदलने से तिब्बती जनता की आकांक्षाओं और आवाज़ के प्रतिनिधित्व की वैधानिकता को खत्म किए बिना केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के इस बुनियादी स्थिति फिर से पुष्ट हुई है।